



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1545]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 4, 2008/कार्तिक 13, 1930

No. 1545]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 4, 2008/KARTIKA 13, 1930

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2008

का.आ. 2594(अ)—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्पूर्ण असम राज्य को दिनांक 27.11.1990 की अधिसूचना का.आ. 916 (अ) के तहत दिनांक 27.11.1990 से 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था;

और, यतः, केन्द्रीय सरकार ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में सीमा से 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था;

और, यतः, वह अवधि जिसके दौरान असम राज्य तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में सीमा से 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषणा को असम राज्य तथा पूर्वोक्त क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद समय-समय पर बढ़ाया गया था;

और, यतः, असम तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों में 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी में कानून एवं व्यवस्था की आगे और समीक्षा करने से निम्नलिखित इंगित होता है :-

- असम में, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) द्वारा की गई अनेक हिंसक वारदातों के कारण खराब रही है। अन्य विद्रोही संगठन जैसे नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोरोलैण्ड (एन डी एफ बी), यूनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक सोलिडैरिटी (यू पी डी एस) कार्बी लोंगरी एन.सी. हिल्स लिबरेशन फ्रंट (के एल एन एल एफ), जो पूर्व

में यू पी डी एस-वार्ता विरोधी गुट के नाम से जाना जाता था, कुकी रिवोल्यूशनरी आर्मी (के आर ए) तथा दीमा हलाम दाओगाह के दोनों गुट - (डी एच डी एवं डी एच डी/जे) भी असम राज्य में हिंसा में काफी हद तक संलिप्त रहे हैं।

- ii) अप्रैल, 2008 से 15 अक्टूबर, 2008 के दौरान असम में हुई हिंसा की 168 घटनाओं में भूमिगत संगठनों द्वारा 04 सुरक्षा बल कार्मिकों सहित 84 व्यक्तियों की हत्याएं की गईं।
- iii) इन सभी संगठनों का विश्वास सशस्त्र संघर्ष में कायम है तथा ये आम जनता में डर पैदा करने, प्रशासनिक प्रणाली को अस्त-व्यस्त करने तथा जनता से जबरन धन वसूली करने के लिए हिंसा के कृत्यों में संलिप्त हैं।
- iv) अरुणाचल प्रदेश के अंदर 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी में आने वाले क्षेत्रों, विशेष रूप से तीरप, चांगलैण्ड, लोहित, पूर्वी एवं पश्चिमी सियांग और निचले दिबांग घाटी जिलों में उग्रवादी गतिविधियों तथा विभिन्न उग्रवादी संगठनों (अरुणाचल प्रदेश तथा असम में सक्रिय) तथा सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ों के कारण कानून एवं व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है। एन एस सी एन के गुट असम-अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में जबरन धन वसूली में संलिप्त हैं। एन एस सी एन-आईएम यह दावा करता है कि इन इलाकों के लोग तथा क्षेत्र उसके प्रस्तावित 'वृहद् नागालिम' का हिस्सा हैं। इसी प्रकार, एन एस सी एन-के, चांगलांग जिला की सीमा से लगे असम के कतिपय भागों को अपने प्रभाव का क्षेत्र होने का दावा करता है। इन संगठनों द्वारा जबरन धन वसूली हेतु बनाए गए लक्ष्यों में व्यापारिक समुदाय, स्थानीय लोग, सरकारी पदाधिकारी तथा क्षेत्र में कार्य कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम भी शामिल हैं।
- v) सुरक्षा बलों द्वारा की गई सतत् कार्रवाई के कारण मेघालय में मौजूदा सुरक्षा तथा कानून एवं व्यवस्था परिदृश्य में सुधार देखा गया है। तथापि, असम की सीमा से सटी 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी में भूमिगत संगठन सक्रिय बने हुए हैं। इस क्षेत्र का बंगलादेश से घुसपैठ/जाने के मार्ग के रूप में और गारो हिल्स से होकर असम को उस देश से शस्त्र/गोलाबारूद की तस्करी करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। यह जानकारी हुई है कि उल्फा इस क्षेत्र का इस्तेमाल आश्रय/छिपने के ठिकानों और शस्त्र/गोलाबारूद/विस्फोटक खेप भेजने तथा प्राप्त करने के लिए करता रहा है।

अतः, अब, सम्पूर्ण असम राज्य तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों की 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत 4.5.2009 तक 'अशांत क्षेत्र' बना रहेगा जब तक कि इस धारा को इससे पहले ही हटा न लिया जाए।

[फा. सं. 11011/38/98-एनई-IV]

नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2008

**S.O. 2594(E).**—Whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the entire State of Assam as 'disturbed area' with effect from 27.11.1990 vide Notification SO 916 (E) dated 27.11.1990.

And whereas the Central Government in exercise of power conferred by Section 3 of the aforesaid Act had also declared besides other areas, the areas falling within 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam as 'disturbed area'.

And whereas the period during which the State of Assam and areas falling within 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam shall be 'disturbed area' under the aforesaid Act was extended from time to time after reviewing the law and order situation in the State of Assam and aforesaid areas.

And whereas a further review of the law and order situation in Assam and 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya bordering Assam indicates the following:-

- i) The law and order situation in Assam has continued to remain grim due to a large number of violent incidents by United Liberation Front of Asom (ULFA). Other insurgent outfits like National Democratic Front of Boroland (NDFB), United Peoples'

Democratic Solidarity (UPDS) Karbi Longri N.C. Hills Liberation Front (KLNLF), earlier known as UPDS - anti talk faction), Kuki Revolutionary Army (KRA) and the two factions of Dima Haram Daogah - (DHD & DHD/J ) were also involved in violence to some extent in the State of Assam.

- ii) During April 2008 to 15<sup>th</sup> October 2008, 84 persons including 04 Security Forces Personnel were killed by the Under Ground outfits in 168 incidents of violence in Assam.
- iii) All these outfits continue to affirm their faith in armed struggle and indulge in acts of violence to create panic among the common people, disturb the administrative system and to extort money from the people.
- iv) The areas falling in the 20 Kms wide belt inside Arunachal Pradesh have witnessed deterioration in law and order due to militant activities and encounters between different militant organizations ( operating in Arunachal Pradesh and Assam) and Security Forces particularly in the districts of Tirap, Changlang, Lohit, East and West Siang and Lower Dibang Valley districts. The NSCN factions are involved in extortion activities in the Assam-Arunachal border areas. The NSCN-IM claims the people and territory of these areas as part of its proposed 'Greater Nagalim'. Similarly, NSCN-K claims certain parts of Assam bordering Changlang district as its sphere of influence. The targets of extortion by the outfits include the business community, local people, government officials and also PSU operating in the area.
- v) The current security and law & order scenario in Meghalaya has shown improvement due to sustained operations by the Security

Forces. However, Under Ground Outfits continue to be active in the 20 km wide belt bordering Assam. The region is used as an infiltration/exfiltration route from/to Bangladesh and for smuggling of arms / ammunition from that country to Assam via Garo Hills. ULFA has been known to be using this area for shelter/hideouts and trans-shipment of arms/ammunition /explosive consignment.

Now, therefore the entire State of Assam and 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya bordering Assam shall continue to be 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 upto 4.5.2009 unless withdrawn earlier.

[F.No.11011/38/98-NE-IV]

NAVEEN VERMA, Jt. Secy.